

प्रेस नोट

आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई का XVIII दीक्षांत समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न

भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., मुंबई देश में मात्स्यिकी उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र है। इसे दुनिया का एकमात्र संस्थान होने की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है जो मत्स्य पालन के 11 अत्यधिक विशिष्ट विषयों में मास्टर और डॉक्टरेट छात्र तैयार करता है। इसने देश में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई तकनीकें भी विकसित की हैं।

भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं. मुंबई ने 8 मार्च 2025 को डिग्री प्रदान करने के लिए अपना XVIII दीक्षांत समारोह मनाया। इस दीक्षांत समारोह में भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., मुंबई के निदेशक एवं कुलपति डॉ. रविशंकर सी.एन. ने 91 मास्टर और 51 पीएचडी छात्रों को डिग्री प्रदान की।

इस अवसर पर माननीय श्री जॉर्ज कुरियन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री; समारोह के मुख्य अतिथि थे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आईसीएआर के उप महानिदेशक (मत्स्य विज्ञान) डॉ. जॉयकृष्ण जेना एवं शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएसटी), श्रीनगर के कुलपति डॉ. प्रोफेसर नजीर अहमद गनई भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने एक संपन्न और तेजी से बढ़ते क्षेत्र का समर्थन करते हुए पेशेवर मत्स्य पालन शिक्षा की भूमिका की सराहना की, जो पूरे भारत में 28 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। वैश्विक स्तर पर, कैप्चर फिशरीज और एकाकल्चर मछली उत्पादन में समान रूप से योगदान दे रहे हैं, जो एक प्रतिमान बदलाव का संकेत देता है, जिसमें अधिक जोर उन्नत जलीय कृषि उत्पादन प्रणालियों पर रहता है जो पानी और ऊर्जा का संरक्षण और पुनर्चक्रण करते हैं, आनुवंशिक रूप से उन्नत उपभेदों, कुशल फ़ीड और स्वास्थ्य प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करते हैं। यह तथ्य मत्स्य पालन पेशेवरों के लिए सुनहरे अवसर प्रस्तुत करता है वास्तव में, CIFE, अन्य ICAR मत्स्य संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों ने उन्नत तकनीकें विकसित की हैं जो उद्यमों को जन्म दे सकती हैं। उन्होंने छात्र उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए CIFE के प्रयासों की सराहना की जो भारत को सेवा अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में योगदान देगा और 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के सपने को पूरा करेगा।

मत्स्य पालन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.2% का योगदान देता है, और 2023-24 के दौरान 132 देशों के व्यापारिक साझेदारों के साथ निर्यात आय ₹60,523.89 करोड़ थी। 2019 में शुरू की गई भारत सरकार की प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ने 22 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के ~32 लाख मछुआरों और किसानों को बीमा कवरेज के तहत समर्थन दिया है और लगभग 7 लाख मछुआरों को लीन/प्रतिबंध अवधि के दौरान आजीविका और पोषण सहायता के लिए कवर किया गया है। इस क्षेत्र पर निरंतर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमएमकेएसवाई) को 2024 में लॉन्च किया गया। इन प्रयासों के कारण घरेलू मछली की खपत अब 13.1 किलोग्राम/व्यक्ति है।

उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और पदक जीतने वाले छात्रों को बधाई दी और सीआईएफई से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना कद बढ़ाने का

PRESS NOTE

ICAR-CIFE, Mumbai is a Centre of Excellence in Fisheries Higher Education in the country. It also has the reputation of being the only university in the world that produces master's and doctoral students in 11 highly specialized disciplines of fisheries. It has also developed many technologies to promote the fisheries sector in the country.

ICAR-CIFE celebrated its XVIII Convocation to confer degrees on 8th March 2025. In this Convocation, Director and Vice Chancellor of ICAR-CIFE, Dr. Ravishankar C.N., conferred degrees on 91 Master's and 51 Ph.D. students.

Hon'ble Mr. George Kurian, Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Dairying and Minority Affairs; was the Chief Guest of the function and Guests of Honour, Dr. Joykrushna Jena, Deputy Director General (Fisheries Science), ICAR, and Dr. Prof Nazir Ahmad Ganai, Vice Chancellor, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology (SKUAST), Srinagar also graced the occasion.

The Chief Guest lauded the role of professional fisheries education in supporting a thriving and rapidly growing sector that employs up to 28 million people across India. Globally, capture fisheries and aquaculture are contributing equally to fish production, indicating a paradigm shift, wherein more emphasis rests on advanced aquaculture production systems that conserve and recycle water and energy, utilise genetically improved strains, efficient feed and health management strategies. This fact presents golden opportunities to fisheries professionals, as they are best equipped to become entrepreneurs, and must seize this moment of a booming start-up culture brought in by this government. In fact, CIFE, other ICAR Fisheries Institutes and Agricultural Universities have developed advanced technologies that can lead to enterprises. He appreciated CIFE's efforts to promote student entrepreneurship that will contribute to the transformation of India from a service economy to a knowledge-based economy and fulfil the dream of becoming 'Viksit Bharat' by 2047.

The fisheries sector contributes to nearly 1.2% of India's GDP, and export earnings were ₹60,523.89 crore during 2023-24 with 132 countries as trading partners. Pradhan Mantri *Matsya Sampada Yojana* (PMMSY) of Govt of India, launched in 2019 has supported ~32 lakh fishers and farmers from 22 States and seven UTs under insurance coverage and an almost 7 lakh fishers have been covered for livelihood and nutritional support during the lean/ban period. In continued emphasis on the sector, the Pradhan Mantri *Matsya Kisan Samridhi Yojana* (PMMKSY) was launched in 2024. Due to these efforts the domestic fish consumption is now 13.1 kg/capita.

He congratulated the students who excelled and won medals, and urged CIFE to continue to augment its stature in the field of higher education



